नईदुनिया






# जापान में सिंथेटिक ईंधन तैयार करने की तकनीक पर हो रहा काम

टोक्यो

जापान में हवा और पानी की मदद से पेट्रोल तथा डीजल जैसा सिंथेटिक ईंधन तैयार करने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड लेकर उसे पानी से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया के जरिए तरल ईंधन तैयार किया जाता है। जापान के पास अपने प्राकृतिक तेल और गैस संसाधन सीमित हैं। इसलिए वह लंबे समय से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध कर रहा है। इसी दिशा में जापान की ऊर्जा कंपनी ईएनईओएस ने योकोहामा में एक प्रदर्शन संयंत्र शुरू किया है। यहां हवा से प्राप्त कार्बन डाइआक्साइड और पानी से निकाली गई हाइड्रोजन की मदद से सिंथेटिक ईंधन बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है। इस तकनीक का पहला चरण डायरेक्ट एयर कैप्चर कहलाता है। इसमें विशेष मशीनों की मदद से वातावरण की हवा से कार्बन डाइआक्साइड को अलग किया जाता है। इसके बाद पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में बिजली की मदद से पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन और आक्सीजन अलग किए जाते हैं। यदि इसके लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय बिजली का इस्तेमाल किया जाए, तो ईंधन उत्पादन का कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है।

तीसरे चरण में हवा से प्राप्त कार्बन डाइआक्साइड और पानी से निकाली गई हाइड्रोजन को एक विशेष रिएक्टर में भेजा जाता है। वहां उन्नत उत्प्रेरकों की मदद से फिशर-ट्राप्स संश्लेषण जैसी प्रक्रिया के जरिए तरल हाइड्रोकार्बन तैयार किए जाते हैं। इन्हें आगे पेट्रोल, डीजल या विमान ईंधन जैसे उत्पादों में बदला जा सकता है। इस सिंथेटिक ईंधन की एक खासियत यह बताई जाती है कि इसे मौजूदा इंजनों में इस्तेमाल करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ सकती। इसे ड्राप-इन फ्यूल कहा जाता है। इसका मतलब है कि निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाला ईंधन पारंपरिक ईंधन की तरह मौजूदा वाहनों और मशीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में इस तकनीक से तैयार ईंधन के परीक्षण और सीमित उपयोग पर काम किया जा रहा है। पर्यावरण के लिहाज से इस तकनीक की अहमियत इसलिए है, क्योंकि ईंधन बनाने के दौरान पहले वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड ली जाती है। जलने पर यह कार्बन फिर वातावरण में लौट सकती है। यदि पूरी प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो, तो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में नए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की संभावना बन सकती है।

हालांकि, इस तकनीक के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। कार्बन डाइआक्साइड को हवा से अलग करना, पानी से हाइड्रोजन बनाना और फिर ईंधन तैयार करना काफी ऊर्जा और खर्च मांगता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन को किफायती बनाना भी आसान नहीं है। इसलिए इसे कच्चे तेल का तत्काल विकल्प नहीं माना जा सकता। फिर भी भविष्य में तकनीक सस्ती और व्यापक होने पर परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मालूम हो कि दुनिया के कई देश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं।

## न्यूज ब्रीफ

### स्टारशिप राकेट रिकवरी टेस्ट में नहीं मिली सफलता, एलन मस्क की उम्मीदों को झटका



वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स को अपने स्टारशिप राकेट के महत्वाकांक्षी परीक्षण में बड़ा झटका लगा है। कंपनी अपने स्टारशिप राकेट के दोनों हिस्सों को एक ही मिशन में वापस हासिल करने की कोशिश में सफल नहीं हो पाई। परीक्षण के दौरान राकेट का सुपर हेवी बूस्टर खाड़ी में जा गिरा, जिसके बाद तकनीकी समस्या के कारण इसे वापस हासिल करने का प्रयास छोड़ दिया गया। यह मिशन पहली बार स्टारशिप के बूस्टर और ऊपरी हिस्से, दोनों को सुरक्षित वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। यह स्पेसएक्स का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी स्टारशिप परीक्षण था। करीब 22 घंटे के इस मिशन का मुख्य मकसद भविष्य में राकेट के दोनों हिस्सों को सफलतापूर्वक इस्तेमाल के लिए वापस लाना था। स्पेसएक्स की योजना पूरे स्टारशिप राकेट को पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने की है। कंपनी का मानना है कि ऐसा होने पर अंतरिक्ष अभियानों की लान्चिंग प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है, जिससे चंद्रमा और मंगल ग्रह से जुड़े भविष्य के मिशनों को बड़ी मदद मिलेगी। अगर यह परीक्षण सफल रहता, तो अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए किसी राकेट के सभी हिस्सों को वापस हासिल कर दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में यह पहली बड़ी उपलब्धि होती। एलन मस्क के लिए राकेट की पूर्ण पुनः उपयोग क्षमता बेहद अहम है। उनका मानना है कि चंद्रमा पर बेस बनाने और इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए बार-बार और कम समय के अंतराल पर राकेट लान्च करना जरूरी होगा। इससे पहले सितंबर में हुए परीक्षण में स्टारशिप पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था, हालांकि उस दौरान कंपनी ने राकेट के किसी भी हिस्से को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं की थी।

### अमेरिकाः उड़ानों पर लगी रोक 4 घंटे बाद हटाई गई, 8 हजार उड़ानें रद्द



वाशिंगटन। अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कम्युनिकेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण करीब चार घंटे देशभर में विमानों की उड़ान रोकनी पड़ीं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने सुरक्षा कारणों से देशभर के एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकने का आदेश दिया था। हालांकि चार घंटे बाद उड़ानों पर लगी रोक हटा दी गई। एफएए के इस आदेश इस दौरान 8,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं और करीब 15 लाख यात्री प्रभावित हुए। सामान्य स्थिति बहाल होते-होते शनिवार को भी काफी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया है कि अबतक किसी साइबर हमले के संकेत नहीं हैं और यह स्थिति 9/11 जैसी नहीं है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि देशभर के हवाई अड्डों पर लागू किए गए ग्राउंड स्टाप के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा होने के संकेत नहीं मिले हैं और यह दूरसंचार व्यवस्था में आई बाधा है। उन्होंने यात्रियों और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद यह दूसरा मौका है जब देशभर में उड़ानों का संचालन एक साथ व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है।

### शरजील विवादः यूएस आयोग की टिप्पणी पर भारत ने किया पलटवार

वाशिंगटन। अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत ने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग की टिप्पणी को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए कहा कि उसे भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग(यूएससीआईआरएफ) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में शरजील इमाम को एक मुस्लिम व्यक्ति बताया, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इमाम की प्रोफाइल का लिंक भी साझा किया। भारत की ओर से इस पर त्वरित प्रतिक्रिया आई। राजदूत क्वात्रा ने एक्स पर लिखा कि यूएससीआईआरएफ की आदतन पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियां भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं। उन्होंने आयोग को सलाह दी कि वह दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुर्खियों में आए थे। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उनके भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई।

# विश्व जलवायु सम्मेलन में हिमालयी मुद्दों पर पीछे नहीं हटा नेपाल, एजेंडे के जरिए रखीं प्रमुख मांगें

काठमांडू

विश्व जलवायु सम्मेलन में हिमालयी मुद्दों को अलग औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद नेपाल ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तुर्किये के अंताल्या में जारी सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय वार्ताओं में नेपाल हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और तकनीकी क्षमता विकास की मांग लगातार उठा रहा है।

नेपाल जलवायु वित्त के मामले में विकसित देशों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठा रहा है। नेपाल का कहना है कि विकसित देशों ने आर्थिक सहायता के जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों में पर्याप्त धनराशि नहीं है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के नाम पर विकासशील देशों पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

नेपाल ने जलवायु संकट के साथ उससे पैदा होने वाले आर्थिक अवसरों का मुद्दा भी उठाया है। दुनिया जब तेल, गैस और कोयले के बजाय स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रही है तो नेपाल जैसे देशों को भी निवेश, तकनीक और आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। COP-31 में शामिल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार, नेपाल ने हाल के दौर की वार्ताओं में इन मुद्दों को समेटते हुए एजेंडा पेश किया है।

**जलवायु संकट की गंभीरता स्वीकार करना** – नेपाल का पहला मुद्दा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। बाढ़, हिमनदों के टूटने, सूखा, पानी की कमी और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं में वृद्धि का उल्लेख करते हुए नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। इसमें हिमालयी क्षेत्रों के साथ समुद्र और बर्फ से ढके अन्य क्षेत्रों में बढ़ते जोखिम भी शामिल हैं। नेपाल की चिंता




केवल हिमनदों के पिघलने तक सीमित नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में होने वाले बदलावों का असर निचले इलाकों की नदी प्रणालियों, सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत और बस्तियों पर भी पड़ सकता है। किसी क्षेत्र में अचानक बड़ी बाढ़ आ सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में पानी की कमी हो सकती है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल इन घटनाओं को अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के रूप में नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे व्यापक जोखिम के रूप में देखने पर जोर दे रहा है।

**हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम** – नेपाल की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करने की है। नेपाल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया के तहत हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं पर केंद्रित नियमित कार्य करने की व्यवस्था बनाई जाए। इसमें हिमालयी क्षेत्र के जलवायु संकट से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की जरूरत है, वर्तमान में कितनी कमी है और किस तरह की तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे विषय शामिल हैं।

हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता पर वैज्ञानिक अध्ययन बढ़ाने की मांग भी की गई है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिमालयी क्षेत्र के बढ़ते जोखिमों पर केवल चर्चा न हो बल्कि उनके समाधान के लिए नियमित काम करने वाला तंत्र भी बनाया जाए। इसमें जलवायु अनुकूलन की सीमाओं का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और अन्य उपायों के जरिए प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कम किया जा सकता है लेकिन सभी उपाय अपनाने के बावजूद कुछ नुकसान पूरी तरह रोकना संभव नहीं होता। नेपाल ने हिमालयी क्षेत्र के ऐसे विशिष्ट जोखिमों को अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों में मान्यता देने की मांग की है।

**जलवायु संकट रोकने और उसके प्रभावों से बचाव के प्रयास पर्याप्त नहीं** – नेपाल का तीसरा एजेंडा अब तक किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की कमियों से संबंधित है। नेपाल का कहना है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने, आपदाओं के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने और इसके लिए आर्थिक एवं तकनीकी संसाधन जुटाने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसमें जलवायु अनुकूलन के लिए धन की कमी के साथ मौसम और जलवायु की नियमित निगरानी तथा आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों का मुद्दा भी उठाया गया है। नेपाल के लिए यह मुद्दा सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है।

हिमझीलों के संभावित खतरे का पता लगाने के लिए नियमित वैज्ञानिक निगरानी जरूरी है। भारी बारिश या अचानक बाढ़ की आशंका पहचानने के लिए विश्वसनीय मौसम संबंधी आंकड़े और पूर्व चेतावनी प्रणाली आवश्यक हैं। लेकिन पर्याप्त उपकरण, अनुसंधान, दक्ष जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों के अभाव में जोखिम की पहचान और उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उत्सर्जन कम करने के प्रयास तेज करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

**आर्थिक मदद हासिल करना आसान बने, कर्ज का बोझ नहीं** – नेपाल की चौथी मांग जलवायु वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता की जरूरत है। लेकिन इस धनराशि को प्राप्त करना मुश्किल होता है, निवेश जुटाना महंगा पड़ता है और कई बार देशों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। नेपाल ने इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त, नियमित, अनुदान आधारित और अत्यधिक रियायती वित्तीय सहायता की मांग की है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शुक्र को छोटे द्वीपीय देशों और अल्पविकसित देशों की जलवायु वित्त संबंधी जरूरतें और वित्त तक पहुंच विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, जलवायु उत्थानशीलता ऋण की स्थिरता की कीमत पर हासिल नहीं की जानी चाहिए। हमें व्यावसायिक ऋण नहीं बल्कि पूर्वानुमान योग्य सार्वजनिक अनुदान और अत्यधिक रियायती वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।

इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावित देशों को उसी काम के लिए महंगा कर्ज लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नेपाल में हिमझीलों के जोखिम को कम करने, बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने, सुरक्षित सड़क और पुल बनाने तथा आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। इन कार्यों के लिए लिए गए कर्ज का मूलधन और ब्याज चुकाने से भविष्य में देश पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

# अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों को वर्क वीजा का विस्तार कराना होगा मुश्किल




**नए प्रस्ताव के तहत वीजा एक्सटेंशन की जांच प्रक्रिया और सख्त करने की तैयारी**

वाशिंगटन

अमेरिका में काम कर रहे हजारों एच-1बी वीजा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों को वर्क वीजा का विस्तार कराना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक नए प्रस्ताव के तहत वीजा एक्सटेंशन की जांच प्रक्रिया सख्त करने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के अधिकारियों के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वे उसी नियोक्ता, कर्मचारी और नौकरी के लिए पहले दी गई वीजा मंजूरी को दोबारा आवेदन की जांच करते समय आधार मानें।

डीएचएस के अनुमान के मुताबिक इस बदलाव से हर साल करीब 2,08,429 याचिकाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिनमें एच-1बी, एल-1, ओ-1, टीएन और ई श्रेणी के वीजा शामिल हैं। यह प्रस्ताव 14 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था और इस पर आम लोगों व संबंधित पक्षों से सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 नवंबर तय की गई थी। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है, जब तक डीएचएस अंतिम नियम जारी कर उसे प्रभावी नहीं करता, तब तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

बता दें वर्तमान नियम के तहत यदि कोई नियोक्ता उसी कर्मचारी, उसी नौकरी और समान परिस्थितियों में वीजा विस्तार के लिए आवेदन देता है, तो यूएससीआईएस आमतौर पर पहले दी गई मंजूरी को महत्व देता है। हालांकि यदि पुराने फैसले में कोई बड़ी गलती सामने आती है, परिस्थितियों में बदलाव होता है या पात्रता से जुड़ी नई जानकारी मिलती है, तो अधिकारी पुराने फैसले से अलग फैसला ले सकते हैं। डीएचएस अब इस व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए प्रावधान को रिजर्व्ड यानी भविष्य के लिए सुरक्षित चिह्नित करने का प्रस्ताव है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो अधिकारी वीजा विस्तार के आवेदन की नए सिरे से जांच कर सकेंगे और उन सवालों पर भी दोबारा विचार कर सकेंगे, जिनका पहले निपटारा हो चुका है। एच-1बी धारकों से ज्यादा दस्तावेज मांगे जा सकते हैं और डीएचएस के मुताबिक फार्म आई-129 के कुल आवेदनों में 75 फीसदी से ज्यादा एच-1बी वीजा से जुड़े होते हैं। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का सबसे ज्यादा असर एच-1बी धारकों पर पड़ सकता है, जिससे हर साल करीब 6,044 अतिरिक्त साक्ष्य के अनुरोध जारी हो सकते हैं।

## पिज्जा पर अनानास डालने को माना जाता है इटलियन खाद्य संस्कृति का अनादर



रोम। आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इतालवी शेफ को कथित तौर पर इसलिए रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने पिज्जा पर अनानास डालने से मना कर दिया था। इस घटना ने खाने-पीने से जुड़ी एक पुरानी बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इटली में पिज्जा पर अनानास डालने का इतना कड़ा विरोध क्यों किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका मुख्य कारण इटैलियन खाद्य संस्कृति में पुरानी रेसिपी और खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों को सहेजकर रखने का महत्व है। पारंपरिक व्यंजन पीढ़ियों से चले आ रहे खान-पान के अनुभव को दर्शाते हैं, जहाँ किसी भी चीज़ को किसी के भी साथ मिलाना स्वीकार्य नहीं होता। इस नज़रिए से, पिज्जा पर अनानास डालने को इस व्यंजन के इतिहास और पहचान का अनादर माना जाता है। एक और बड़ी आपत्ति स्वाद को लेकर है। पारंपरिक इटैलियन पिज्जा का स्वाद आमतौर पर नमकीन, तीखा और हल्का खट्टा होता है, जिसमें टमाटर की मुख्य भूमिका होती है। जबकि अनानास मिलाने से इसमें काफ़ी मिठास और खटास आ जाती है। जानकारों का तर्क है कि अनानास का स्वाद इतना तेज़ होता है कि यह टमाटर सास और मोज़रेला चीज़ के स्वाद को दबा देता है।

# जासूसी की बात स्वीकारने पर तांग को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

**बचाव पक्ष के वकील ने कहा- तांग लोकतंत्र समर्थक, लेखक और कार्यकर्ता**

बीजिंग

न्यूयार्क में चीन के असंतुष्ट समुदाय के एक सदस्य को अपने साथी कार्यकर्ताओं की पांच साल तक चीन सरकार के लिए जासूसी करने की बात स्वीकार करने के बावजूद मैनहट्टन की संघीय कोर्ट ने जेल की सजा नहीं सुनाई। युआनजुन तांग (69) तीन दशक से ज्यादा समय से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं। न्यायाधीश जान जी कोएल्टल ने उन्हें तीन साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने कहा कि कुछ लोगों के इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी कि तांग की गतिविधियों के कारण उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सहायक अटार्नी जेन चोंग ने न्यायाधीश से तांग को पांच साल की जेल की सजा देने का अनुरोध किया था। तांग ने सितंबर 2025 में इस आरोप को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने अमेरिकी अटार्नी जनरल के कार्यालय में चीन सरकार के एजेंट के रूप में अपना पंजीकरण नहीं कराया था। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल लोकतंत्र समर्थक, लेखक और कार्यकर्ता हैं। वह अपने बीमार माता-पिता और




भाई से मिलने के लिए चीन लौटने की बेहद इच्छा रखते थे और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें चीन जाने में मदद करने का भरोसा दिलाया था।

रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने कहा कि तांग को चीन पहुंचने के बाद ही पता चला कि वह व्यक्ति जासूस था। वहां पहुंचने पर उन्हें यह भी पता चला कि उनकी मां और भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी। तांग ने कहा कि उन्होंने चीन जाकर अपने माता-पिता से मिलने की इच्छा में अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा है। मेरे कार्यों से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है। तांग को अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले चीन की ओर से विदेशों में असंतुष्टों को परेशान करने और उनकी आवाज दबाने की कोशिशों से जुड़े कई चर्चित मामलों की जांच हुई थी। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक एक चीनी खुफिया अधिकारी के निर्देश पर तांग चीन के खिलाफ होने वाले स्थानीय विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें लेने और उनकी रिकार्डिंग करने के लिए सहमत हो गए थे।

# इश्क या लड़की के चक्कर में रातों-रात कई कंपनियों के बास को चुकानी पड़ी बड़ी कीमतें

**जेनसन ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, कार्पोरेट इतिहास में कुर्सी गंवाने वाले वह अकेले नहीं**

न्यूयार्क

टेक दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ और को-फाउंडर जेनसन हुआंग ने कंपनी के सीईओ समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐलिस हुआंग नाम की महिला से अफेयर के कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ऐलिस सिंगापुर की कंपनी मेगस्पीड में वरिष्ठ पद पर काम करती हैं और शक है कि वे चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हैं, लेकिन कार्पोरेट इतिहास में जेनसन हुआंग अकेले ऐसे दिग्गज नहीं हैं, जिन्हें इश्क या दफ्तर में बने रिश्तों की कीमत अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी हो। हुआंग से पहले भी कई बड़ी कंपनियों के बास लड़की के चक्कर में रातों-रात बाहर का रास्ता देख चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक जेनसन हुआंग का मामला अन्य सीईओ से अलग और गंभीर है। नौकरी मुख्य रूप से कंपनी की पालिसी और कार्पोरेट आचरण के उल्लंघन की वजह से गई, वहीं जेनसन हुआंग के मामले में नेशनल सिक्योरिटी का भी पेंच फंसा है। यह मामला अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। अमेरिकी सांसद उनसे एलिस हुआंग के साथ उनके संपर्कों और एनवीडिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछने की तैयारी में हैं।

बता दें एनर्जी कंपनी बीपी के पूर्व सीईओ बर्नार्ड लूनी जेनसन के बाद वह बड़ा नाम है, जिनको इश्क के चक्कर में नौकरी गंवानी पड़ी। सितंबर 2023 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कंपनी की आंतरिक जांच में यह बात सामने आई थी कि लूनी के अपने आफिस की लड़कियों से अफेयर्स थे। इस विवाद के बाद कंपनी की साख और कार्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठे। इसके बाद कंपनी ने लूनी को बाहर का




रास्ता दिखाया और उनके वेतन और भत्तों के एक बड़े हिस्से की वसूली तक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी फूड और बेवरेज कंपनी नेस्ले ने सितंबर 2025 में अपने सीईओ लारेंट फ्रीक्स को बर्खास्त कर दिया था। कंपनी की जांच में खुलासा हुआ कि फ्रीक्स का अपने ही अधीन काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से प्रेम संबंध थे और उन्होंने इस बात को कंपनी से छिपाकर रखा। नेस्ले ने इसे व्यावसायिक आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना। वहीं फास्ट-फूड चेन मैकडानल्ड्स ने नवंबर 2019 में अपने सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी को पता चला कि ईस्टरब्रुक का एक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध था, जो कंपनी की नीतियों के खिलाफ था। मामला यहीं नहीं रुका, बाद में एक कानूनी समझौते के तहत ईस्टरब्रुक को कंपनी से मिले पैकेज की एक बड़ी रकम भी वापस करनी पड़ी थी। टेक्नोलाजी कंपनी एस्ट्रोनामर के सीईओ एंडी बायरन की कुर्सी छीन ली थी। जुलाई 2025 में एक कोल्डप्ले कान्सर्ट के दौरान उनका अपनी ही कंपनी की एक महिला कर्मचारी को गले लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया।